पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) संख्या- 167

वर्ष 2015 का थाना कांड संख्या- 16 से उत्पन्न

==========

समीर कुमार सिन्हा, श्री सुरेन्द्र प्रसाद के पुत्र, निवासी ग्राम- पटौर लाल, थाना- मोतीहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, वर्तमान में पूर्वी चंपारण दरियापुर, ब्लॉक, सारण रेलवे क्वार्टर, छपरा, वर्तमान में गंगा कॉम्पलेक्स फलैट संख्या- 406, कंकड़बाग मुख्य सड़क, थाना- कंकड़बाग, जिला-पटना

.....अपीलाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादीगण

==========

अधिनियम/धाराएं/नियमः

- आईपीसी-धारा 304 बी
- दंड प्रक्रिया संहिता-धारा 161,164,313
- साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 32 (1), 113 बी, 118,134

संदर्भित मामलेः

- शेर सिंह उर्फ प्रताप बनाम हरियाणा राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 724 में रिपोर्ट किया गया
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर ने (2000) 8 एस. सी. सी. 382 में रिपोर्ट किया
- सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य ने (2009) 14 एस. सी. सी. 415 में रिपोर्ट किया
- रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य रिपोर्ट (2007) 13 एस. सी. सी. 501

- (2001) 9 एस. सी. सी. 704 में रिपोर्ट किए गए जंग सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य
- सेकरन बनाम तमिलनाडु राज्य (2024) 2 एस. सी. सी. 176 में रिपोर्ट किया गया
- पी. रमेश बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक ने (2019) 20 एस. सी. सी. 593 में किया।
- रूदल चौपाल बनाम बिहार राज्य 2024 में रिपोर्ट किया गया (2) बी. एल. जे. 131 (एच. सी.)
- मलकियत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 341

अपील-आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने के लिए

मुखबिर ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को उसके पति (अपीलार्थी) ने जला दिया था

आयोजित-अभिलेखों पर यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी जब वह जल रही थी और उक्त प्रयास में उसे चोटें आई थीं। (पैरा 57)

अभियोजन पक्ष ने पहली बार में यह स्थापित नहीं किया है कि दहेज की मांग के संबंध में पीड़ित को उसके पति (अपीलकर्ता) द्वारा प्रताड़ित किया गया था और घटना से कुछ समय पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और परेशान किया गया था, इसलिए, इस मामले में, बचाव पक्ष द्वारा खंडन के भारी बोझ की आवश्यकता वाली कानूनी धारणा उत्पन्न नहीं होगी। (पैरा 58)

दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। (पैरा 59)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) संख्या- 167

वर्ष 2015 का थाना कांड संख्या- 16 से उत्पन्न

==========

समीर कुमार सिन्हा, श्री सुरेन्द्र प्रसाद के पुत्र, निवासी ग्राम- पटौर लाल, थाना- मोतीहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, वर्तमान में पूर्वी चंपारण दरियापुर, ब्लॉक, सारण रेलवे क्वार्टर, छपरा, वर्तमान में गंगा कॉम्पलेक्स फलैट संख्या- 406, कंकड़बाग मुख्य सड़क, थाना- कंकड़बाग, जिला-पटना

.....अपीलाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री विजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री सत्येंद्र कुमार भटनागर, अधिवक्ता
		श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
		श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता
		श्री कुमार शिवम सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक
मुखबिर के लिए	:	सुरेश कुमार, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति अनुपमा चक्रवर्ती

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांकः 07.03.2024

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सत्येंद्र कुमार भटनागर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा और सूचना देने वाले का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री सुरेश कुमार की सहायता से विद्वान वकील श्री विजय कुमार सिन्हा को सुना गया।

2. इस अपील को दिनांकित 01.12.2017 के फैसले और दिनांकित 12.12.2017 के आदेश को दरकिनार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-**IV**-सह-विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 371 (2016 का सी. आई. एस. संख्या 459,2015 के कंकड़बाग थाना मामले संख्या 734 से उत्पन्न) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

<u>अभियोजन मामला</u>

3. अभियोजन पक्ष का मामला पीड़ित के पिता हरेश कुमार श्रीवास्तव (पीडब्लू-4) के *फरदबेयान* पर आधारित है। अगमकुआं थाना के सब-इंस्पेक्टर (एस. आई.) के. के. सिंह द्वारा 8 बजे सुबह 27.10.2015 को दर्ज किए गए अपने फरदबेयान में, मुखबिर ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी नम्रता को उसके पति समीर कुमार सिन्हा ने कंकड़बाग थाना के भीतर गंगा परिसर के फ्लैट संख्या- 406 में मिट्टी का

तेल डालकर और माचिस से आग लगाकर जला दिया था। उसकी बेटी घायल हो गई थी, उसे पड़ोसियों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल लाया गया और उनके द्वारा उसे सूचित किया गया। 27.10.2015 को इलाज के दौरान उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। *फर्दबयान* को अपोलो बर्न अस्पताल, कुम्हरार, कंकड़बाग, पटना में मुखबिर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। मुखबिर ने आगे आरोप लगाया कि उक्त घटना का कारण यह है कि डेढ़ साल पहले उसकी बेटी की शादी हिंदू संस्कार और रीति-रिवाज के अनुसार अपीलार्थी के साथ हुई थी। और उक्त विवाह में, उन्होंने लगभग दस लाख रुपये खर्च किए। लेकिन शादी के बाद दो लाख रुपये की मांग और एक मोटरसाइकिल की मांग की गई जा रही थी जिसे उनकी बेटी पूरा नहीं कर सकी। मुखबिर ने दावा किया कि उसकी बेटी बार-बार उसे इस बारे में बता रही थी और कल 26.10.2015 को लगभग 4:00 बजे शाम को उसकी बेटी ने पैसे के लिए फोन किया था और कहा था कि अगर पैसे उपलब्ध नहीं कराए गए तो उसे मार दिया जाएगा। मुखबिर ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी से कहा कि वह 27.10.2015 को आएगा और उसे मना लेगा। मुखबिर के अनुसार, यह घटना इसलिए हुई क्योंकि पैसा और सामान उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

4. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि 27.10.2015 को, स्टेशन हाउस ऑफिसर (**S. H. O.**), अगमकुआं थाना ने *फर्दब्यान* को एस.एच.ओ. कंकड़बाग थाना को भेज दिया क्योंकि घटना का स्थान कंकड़बाग थाना के अधिकार क्षेत्र में स्थित था। उक्त *फरदबेयान* के आधार पर, कंकड़बाग थाना द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत 2015 का कंकड़बाग थाना मामला संख्या 734 दिनांक 28.10.2015 के रूप में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (संक्षेप में 'एफ. आई. आर.') दर्ज की गई थी। औपचारिक प्राथमिकी से पता चलता है कि जानकारी कंकड़बाग थाना में 18:45 बजे 28.10.2015 को प्राप्त हुई थी, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक साथ दर्ज की गई और मामले की जाँच विजय कुमार मिश्रा उप पुलिस निरीक्षक को सौंप दी गई। हालाँकि, पटना के विद्वान

न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 31.10.2015 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त हुई थी।

5. जाँच के बाद, पुलिस ने एकमात्र आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत आरोप पत्र समर्पित किया। विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 06.04.2016 के आदेश के *माध्यम* से संज्ञान लिया गया था। चूंकि कथित अपराध एक सत्र विचारण योग्य अपराध था, इसलिए अभिलेखों को दिनांक 27.04.2016 के आदेश के *माध्यम* से सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। तदनुसार, अभिलेख निपटान के लिए पटना के विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्राप्त किए गए थे। इस मामले में आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत एकमात्र आरोपी के खिलाफ 17.09.2016 को आरोप तय किया गया था। उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. अभियोगों को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की जो इस प्रकार हैंः **.**

पीडब्लू-1 विमलेश कुमार (मृतक के चाचा), पीडब्लू-2 कीर्ति प्रसाद वर्मा (मृतक के पिता का सह-भाई होने के नाते उसका रिश्तेदार), पीडब्लू-3 नितीश कुमार सिंह (पिछले वर्षों से अपने पिता का परिचित), पीडब्लू-4 हरेश कुमार श्रीवास्तव (मुखबिर), पीडब्लू-5 खुशी कुमारी (बाल गवाह, जो मृतक के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है और प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करती है), डॉ. रामानंद चौधरी (पीडब्लू-6, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर), नवीन कुमार सिंह (पीडब्लू-7), पुलिस-सह-अधिकारी के एस. आई. विजय कुमार मिश्रा (पीडब्लू-8) से जांच का प्रभार लेने वाले कंकड़बाग थाना ने 2016 की आरोप पत्र संख्या 104 के *माध्यम* से आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे प्रदर्श '5' के रूप में चिह्नित किया गया था।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख में लाए गए थे। प्रदर्श '1', '1/1' और प्रदर्श '1/2' क्रमशः विमलेश कुमार, हरेश कुमार श्रीवास्तव और विजय कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर, विरोध-सह-शिकायत याचिका (प्रदर्श-2), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उनके बयान पर खुशी कुमारी के हस्ताक्षर (इसके बाद 'आ.प्र.संहिता' के रूप में संदर्भित) (प्रदर्श-3), शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श-4), 2016 की आरोप पत्र संख्या 104 (प्रदर्श-5), अनुरोध रिपोर्ट (प्रदर्श-6) और धारा 164 आ.प्रक्रिया संहिता के तहत खुशी कुमारी का बयान दर्ज किया गया। हम अभिलेखों से पाते हैं कि बचाव पक्ष की ओर से की गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद विद्वत निचली अदालत द्वारा दिनांक 16.06.2017 के आदेश के *माध्यम* से प्रदर्श '7' को चिन्हित किया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने धारा 164 आ. प्रक्रिया संहिता कथन को अनुमति देते हुए अपने दिनांकित 16.06.2017 के आदेश में देखी गई आपत्ति के साथ प्रदर्श '7' को प्रदर्श किया कि जहां तक तत्काल मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता का संबंध है, इसे अंतिम निर्णय के समय लिया जा सकता है।

8. बचाव पक्ष की ओर से, सात गवाहों से पूछताछ की गई और बचाव पक्ष ने कुछ दस्तावेजों जैसे कि डिस्चार्ज स्लिप, हिस्ट्री शीट और भुगतान बिल दिनांक 09.01.2016 को अभिलेख में लाया, जिन्हें पहचान के लिए 'एक्स', 'एक्स/1' और 'एक्स/2' के रूप में चिह्नित किया गया था। डॉक्टर के हस्ताक्षर प्रदर्शनी 'ए' और प्रदर्शनी 'ए/1' के रूप में लाए गए हैं, अपोलो बर्न अस्पताल के आरोपी-अपीलार्थी के इलाज के दस्तावेज 'बी' से 'बी/15' प्रदर्शित किए गए हैं, छुट्टी पर्ची दिनांक 07.01.2016 को प्रदर्श 'सी' के रूप में चिह्नित किया गया है। 2016 के उत्तराधिकार मामला संख्या 15 की याचिका की प्रमाणित प्रति और इसके आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति क्रमशः 'डी' से 'डी/1' प्रदर्शित की गई है। मिथलेश कुमार (डी. डब्ल्यू. -1) गंगा परिसर में फ्लैट संख्या 406 का मालिक है जिसने इस अपीलार्थी को अपना फ्लैट किराए पर दिया था। निर्मला देवी (डी. डब्ल्यू.-2) उस घर की पूर्व मालिक हैं जिसमें यह अपीलार्थी लगभग दो साल

से अपने माता-पिता के साथ रह रहा था। संतोष कुमार सिंह (डी. डब्ल्यू.-3) डी. डब्ल्यू.-2 का पुत्र है। रेणु देवी (डी. डब्ल्यू.-4) अपीलार्थी की बहन हैं। रिंकी देवी (डी. डब्ल्यू.-5) भी अपीलार्थी की बहन हैं। संजीव कुमार सिन्हा (डी. डब्ल्यू.-6) अपीलार्थी के बड़े भाई हैं और डॉ. संजय कुमार (डी. डब्ल्यू.-7) को अपोलो बर्न अस्पताल का कर्मचारी कहा जाता है, जिन्होंने प्रदर्श 'बी' से प्रदर्श 'बी/15' और प्रदर्श 'सी' प्रमाणित किया है।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

9. निचली अदालत ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने पर पाया कि पीडब्लू-4, जो मामले का सूचना देने वाला है, ने उसके *फरदबेयान* (प्रदर्श '1/3') का समर्थन किया है। उसने कहा है कि लगभग 4 से 5 बजे शाम, उसे अपनी बेटी नम्रता का फोन आया, जिसने कहा कि उसका पति पैसे के लिए झगड़ा कर रहा है और अगर उसे भुगतान नहीं किया जाएगा, तो उसे मार दिया जा सकता है। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचनादाता (पीडब्लू-4) का कथन पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 द्वारा समर्थित है, इसलिए, यह मृतक द्वारा बोला गया एक तथ्य है और यह उस परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसका लेन-देन से संबंध है जो उसकी मृत्यु में समाप्त हुआ। अतः विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह कथन साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसके बाद "1872 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 32 (1) के दायरे में आएगा। विद्वत विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा अपने विचारों का समर्थन **रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1997) 4 एस. सी. सी. 161 और शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 मामलों में किया। कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 5 एस. सी. सी. 207** पर भी भरोसा किया।

10. विद्वत निचली अदालत ने आगे दर्ज किया है कि खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) ने विशेष रूप से कहा है कि घटना की तारीख पर, अपीलार्थी ने पीड़ित/मृतक को

पीटा था। पीडब्लू-5 ने दावा किया कि वह गर्मी के कारण जागी तो उसने पाया कि *दीदी* (पीड़ित लड़की) कमरे में जल रही थी और *भैयाजी* (आरोपी) फोन पर बात कर रहे थे, फिर उसने गेट खोला और *हल्ला* किया, जिस पर लोग आए और जब भैयाजी ने पुरुषों को देखा तो वह आग बुझाने लगा। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। विद्वत ट्रायल कोर्ट ने पाया कि इस गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि उसने लौ को बुझाने के लिए *दीदी* के शरीर पर कंबल रखा था और कंबल को *भैयाजी* ने गार्ड को फेंकने के लिए दिया था। पीडब्लू-5 ने यह भी कहा है कि उसका बयान 25.02.2016 को अदालत में दर्ज किया गया था, उसने उसी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की (प्रदर्श '3')। अपनी जिरह में, उसने खुलासा किया था कि वह समीर कुमार को *भैयाजी* कहती थी और वह अपनी पढ़ाई के लिए उनके साथ रह रही थी। विद्वत ट्रायल कोर्ट ने पाया कि पीडब्लू-5 ने मुखबिर और दुर्भाग्यपूर्ण लड़की के बीच झगड़े के बारे में बताया है। निचली अदालत के अनुसार, पीडब्लू-5 ने धारा 164 आ.प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान की पुष्टि की थी (प्रदर्श- '7')। उसे पहली गवाह के रूप में लिया गया है जिसने घटना को देखा था और यह पाया गया है कि उसने यह भी खुलासा किया था कि नम्रता (मृतक) को उसके पति समीर कुमार सिन्हा ने दहेज के लिए मारने से पहले उस पर हमला किया था।

11. विद्वत विचारण न्यायालय ने आई. ओ. के साक्ष्य पर चर्चा की है। (पीडब्लू-7) और आई. ओ. (पीडब्लू-8)। यह पीडब्लू-8 है जिसने अगमकुआं थाना से हरेश कुमार श्रीवास्तव (पीडब्लू-4) का *फरदबेयान* प्राप्त किया था और उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पीडब्लू-8 ने बचाव पक्ष के गवाहों, राम चरित्र दास और मिथलेश कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में खुलासा किया है, लेकिन विद्वत निचली अदालत ने राम चरित्र दास और मिथलेश कुमार के सबूतों पर गौर करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि वे आरोप पत्र के गवाह नहीं हैं और इसलिए उनके बयानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और इस पर गौर नहीं किया जा सकता है।

अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया, अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर कई आधारों पर हमला किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत निचली अदालत ने मुखबिर (पीडब्लू-4) के बयान को बहुत अधिक प्रमाणिक महत्व देते हुए घोर गलती की है कि उसे लगभग शाम 4 से 5 बजे 26.10.2015 को अपनी बेटी नम्रता का फोन आया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. ओ. के पास टेलीफोन कॉल का सत्यापन किया गया और निचली अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई कि नम्रता ने लगभग शाम 4 से 5 बजे अपने पिता को 26.10.2015 को टेलीफोन पर कॉल किया था।

13. विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए पूरी तरह से गलती की है कि मृतक द्वारा बोले गए शब्द उन परिस्थितियों के संदर्भ में हैं जो उस लेनदेन से संबंधित हैं जो उसकी मृत्यु में समाप्त हुआ और इसलिए, यह 1872 के अधिनियम की धारा 32 (1) के दायरे में आएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही एक पल के लिए यह माना जाए कि मृतक द्वारा बोले गए शब्दों में परिस्थितियों का संदर्भ है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में पूरी श्रृंखला स्थापित होने के अभाव में, यह अप्रतिरोध्य रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि नम्रता की मृत्यु हत्या थी। विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि यद्यपि शरद **बर्डहिचंद सारदा (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विद्वत निचली अदालत के समक्ष रखा गया था, लेकिन विद्वत निचली अदालत इस बात की सराहना

नहीं कर सकी कि 1872 के अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत निकटता परीक्षण हत्या और आत्महत्या दोनों पर लागू होता है।

14. इस न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ '198' की ओर आकर्षित किया गया है। **शरद बर्धीचंद सारदा (उपरोक्त)** के मामले में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा आपराधिक दंड प्रक्रिया 313 के तहत बयान के अवलोकन से, यह देखा जा सकता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के सामने प्रत्येक भौतिक तथ्य नहीं रखा था जिसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाना था और उसे समझाने का कोई मौका नहीं दिया गया था। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मामले में निर्णय के पैराग्राफ '25' में **हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य** ने रिपोर्ट किया **ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 468** में प्रतिवेदित किया को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है।

15. विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि ऐसे कुछ तथ्य हैं जो उन अभिलेखों से स्पष्ट होंगे जो निचली अदालत के समक्ष प्रदर्शित किए गए थे। यह बताया गया है कि पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-4 की उपस्थिति में अपोलो बर्न अस्पताल, कुम्हरार में पुलिस उप-निरीक्षक, अगमकुआं थाना (जांच नहीं की गई) द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार की गई थी। पीडब्लू-1 हस्ताक्षर करने वाले दो लोगों में से एक प्रदर्श 6 पर है। उन्होंने प्रदर्श '2' के रूप में अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जाँच रिपोर्ट में, एक कॉलम है जिसमें उन परिस्थितियों के संबंध में जानकारी की आवश्यकता होती है जो एक गैरकानूनी कार्य संदेह को जन्म दे सकती हैं, "वे परिस्थितियाँ यदि कोई जिससे किसी कुटकर्म का संदेह उत्पन्न हो" "उक्त कॉलम के सामने, एक कट मार्क (एक्स) दिया गया है जो दर्शाता है कि जांच रिपोर्ट तैयार करने के समय, नम्रता की

मौत के संबंध में उसके पति के खिलाफ किसी भी संदेह के बारे में पुलिस को नहीं बताया गया था।

16. यह आगे समर्पित किया जाता है कि यदि इस प्रदर्श '6' को पीडब्लू-4 के साक्ष्य के साथ पढ़ा जाता है, तो यह देखा जाएगा कि पीडब्लू-4 ने 27.10.2015 को ही पटना में अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया और वह मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया, जहाँ से वह तीन दिनों के बाद वापस आया। यह इस कारण से एक प्रासंगिक तथ्य होगा कि हालांकि कहा जाता है कि सूचना देने वाले का *फर्दब्यान* एस. आई. कंकड़बाग थाना द्वारा 27.10.2015 को ही दर्ज किया गया था, लेकिन यह कंकड़बाग थाना तक पहुंच गया, जो अगली तारीख को केवल दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 28.10.2015 को 18:45 बजे इस प्रकार, दोपहर में दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंकड़बाग थाना तक पहुंचने में लगभग पैंतीस घंटे लग गए। इतना ही नहीं, प्रथम सूचना प्रतिवेदन पटना में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 31.10.2015 यानी लगभग तीन दिनों के बाद पहुंची। परीक्षण के दौरान पीडब्लू-7 या पीडब्लू-8 द्वारा देरी की व्याख्या नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, प्राथमिकी केवल एक विचार के बाद और पूर्ववत के रूप में दर्ज की गई है। पीडब्लू-4 ने स्वीकार किया है कि वह एक सांसद के निजी सहायक के रूप में काम कर रहा था। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, पी. डब्ल्यू.-4 के मुज़फ़्फ़रपुर से लौटने के तीन दिन बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यही कारण है कि प्राथमिकी को पूर्ववत कर दिया गया था लेकिन यह केवल 31.10.2015 को ही विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत तक पहुँच सकता था।

17. विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि इस मामले में खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है, जो घटना के समय लगभग नौ साल की उम्र की एक बाल गवाह है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि

खुशी कुमारी मृतक और अपीलार्थी के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी और घटना के दिन वह वहाँ थी। उसने कहा है कि उक्त तिथि पर भी नम्रता और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी ने उसे पीटा था, जिसके बाद नम्रता ने पानी माँगा था और पीडब्लू-5 ने उसे वही दिया था, जिसके बाद उसने अपने माता-पिता से बात की थी और सो गई थी। पीडब्लू-5 को भी अपीलार्थी ने सोने के लिए कहा था और वह सो गई थी। पीडब्लू-5 का दावा है कि वह तब जागी जब उसे गर्मी महसूस हुई और इस स्तर पर उसने पाया कि नर्मदा उसके कमरे में जल रही थी और अपीलार्थी अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। पीडब्लू-5 का दावा है कि उसने दरवाजा खोला था, नीचे जाकर एक हल्ला किया, जिसके बाद कुछ लोग आए और इस स्तर पर जब अपीलार्थी ने पाया कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसने आग की लपटों को बुझाना शुरू कर दिया। पीडब्लू-5 ने कहा है कि पुलिस अस्पताल में आई थी और उससे पूछताछ की थी। विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि पीडब्लू-4 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि पीडब्लू-5 अस्पताल में मृतक के साथ मौजूद था। लेकिन तथ्य यह है कि आई. ओ. द्वारा पीडब्लू-5 की जांच नहीं की गई थी। (पीडब्लू-8) ने 27.10.2015 को पीडब्लू-8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने नौकरानी खुशी कुमारी का बयान दर्ज किया था और उसे धारा 164 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए अदालत में ले गया था। पीडब्लू-8 ने अपने बयान के पैराग्राफ '12' में कहा है कि खुशी कुमारी ने उन्हें बताया था कि नम्रता ने खुद को आग लगा ली थी। यह समर्पित किया जाता है कि खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) को तुरंत जांच के दौरान आई. ओ. के सामने पेश नहीं किया गया था, उसे लगभग 2-3 महीने तक पढ़ाया गया था और फिर उसे बयान देने के लिए पुलिस के सामने लाया गया था। खुशी कुमारी ने खुद अपनी जिरह के पैराग्राफ '8' में कहा है कि उसके पिता उसे पुलिस के सामने बयान देने के लिए लाए थे और उसके पिता के कहने पर वह बयान दे रही थी। उसने यह भी कहा है कि दो-तीन महीने बाद वह बयान देने आई थी।

18. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रदर्श '7', जो कि धारा 164 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीडब्लू-5 का बयान है, के साथ-साथ निचली अदालत में पीडब्लू-5 की गवाही के अवलोकन से, यह प्रतीत होगा कि इस तथ्य के बावजूद कि पीडब्लू-5 एक बाल गवाह है, विद्वान दंडाधिकारी ने बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की। इस मामले में इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ के हाल के एक फैसले का उल्लेख करते हुए। **रूडल चौपाल बनाम बिहार राज्य जिसे 2024 (2) बी. एल. जे. 231** में प्रतिवेदित किया, विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि उक्त मामले में, इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा की आवश्यकताओं पर चर्चा की है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हैः **प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य का मामला 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 777 और पी. रमेश बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक ने (2019) 20 एस. सी. सी. 593 में दर्ज किया।** विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी बच्चे का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। साक्षी घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करके बाल गवाह की क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए।

19. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि धारा 164 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीडब्लू-5 का बयान दर्ज करते समय, विद्वान दंडाधिकारी ने केवल शीर्ष पर दर्ज किया है कि गवाह से कुछ सवाल पूछने के बाद, उनका मानना था कि वह प्रश्नों की प्रकृति को समझें और उनका उत्तर दें। उसके द्वारा देखी गई घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की उसकी क्षमता की जांच करने के लिए बाल गवाह से क्या सवाल किए गए थे, इसका उल्लेख विद्वान दंडाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है,

इसके अलावा, विद्वान न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया है, की सुनवाई के दौरान जांच नहीं की गई है, इसलिए, बचाव पक्ष को उस तरीके की सत्यता का परीक्षण करने का अवसर नहीं मिल सका है जिसमें विद्वान न्यायिक अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों के संबंध में बाल गवाह से पूछे गए प्रश्नों को समझने के लिए सच्चाई बोलने की उसकी क्षमता को समझने के लिए। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, इसने अपीलार्थी के मामले में पूर्वाग्रह पैदा किया है। यह बताया गया है कि मुकदमे के दौरान, भले ही यह गवाह केवल दस साल की उम्र का था, लेकिन विद्वत निचली अदालत ने पीडब्लू-5 से पूछताछ करके उस घटना को समझने और सच बोलने की उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए उसकी क्षमता का पता नहीं लगाया। ऐसी परिस्थिति में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-5 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसे बाहर रखा जा सकता है।

20. विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और अभिलेख पर उपलब्ध बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि सभी गवाहों ने कहा है कि शुरू में सब कुछ ठीक था। पीडब्लू-4 ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि शादी के बाद नम्रता अपने पति के साथ *ससुराल* गई और वह वहाँ लगभग एक सप्ताह तक ठीक थी। अपनी शादी के एक महीने बाद, वह मुजफ्फरपुर के नया तोला में स्थित अपने ससुराल के रेलवे क्वार्टर में स्थानांतरित हो गई थी। सिंडिकेट बैंक में अपनी सेवा के दौरान उन्हें पाकुड़ स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके बाद उन्हें पटना स्थानांतरित कर दिया गया जहां नम्रता अपने पति के साथ कंकड़बाग में गंगा अपार्टमेंट में रह रही थीं। विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि भले ही पीडब्लू-4 ने कहा है कि दो लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल, उसके अपने बयानों से यह प्रतीत होता है कि नम्रता और अपीलार्थी दोनों खुशी से रह रहे थे। जब नम्रता मुज़फ़्फ़रपुर में काम कर रही थी, तो इस अपीलार्थी ने किराए पर एक आवास लिया था और नम्रता के काम को

सुविधाजनक बनाने के लिए मुज़फ़्फ़रपुर में अपना निवास रखते हुए मुज़फ़्फ़रपुर से छापरा तक अपना काम कर रहा था।

21. यह समर्पित किया जाता है कि बचाव पक्ष के सबूत यह दिखाने के लिए हैं कि नम्रता को बचाने के प्रयास में, अपीलार्थी ने भी पच्चीस प्रतिशत तक खुद को जला लिया था और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ से छुट्टी मिलने के बाद उसे पीडब्लू-8 द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इन आधारों पर, अपीलार्थी समर्पित करता है कि विद्वत विचारण न्यायालय के निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने जैसी परिस्थितियों को दिखाने में सक्षम नहीं है कि यह हत्या का मामला है।

<u>राज्य और सूचना देने वाले की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

22. राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक के साथ-साथ सूचना देने वाले के विद्वान वकील ने संयुक्त रूप से इस अपील का विरोध किया है। ज्ञात अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रस्तुत करता है कि यह आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत एक मामला है और इस तरह, सबूत का बोझ अपीलार्थी पर अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए होगा। विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) की उपस्थिति को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है और बचाव पक्ष के गवाहों में से एक, जो अपीलार्थी की बहन है, ने कहा है कि अपीलार्थी अगस्त, 2015 के महीने में अपने घर से मिट्टी का तेल लाया था। यह भी समर्पित किया जाता है कि डॉ. रामानंद चौधरी (पीडब्लू-6) के साक्ष्य के साथ *शव परीक्षण प्रतिवेदन* के रूप में अभिलेख में लाए गए चिकित्सा साक्ष्य मृत्यु के कारण की पुष्टि करते हैं।

23. यह आगे समर्पित किया जाता है कि जहां तक प्राथमिकी भेजने में देरी का संबंध है, यह पुलिस की गलती है, इसलिए, तीन दिनों की देरी के बाद प्राथमिकी

भेजने में पुलिस की गलती के लिए, अभियोजन पक्ष का मामला नहीं गिरेगा। विद्वान वकीलों ने विद्वत विचारण न्यायालय के फैसले का संयुक्त रूप से समर्थन किया है।

विचार

24. अपीलार्थी के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक और मुखबिर के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है। राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी (इसके बाद '1872 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, दहेज मृत्यु के बारे में एक धारणा होगी और कानून की ऐसी धारणा प्रकृति में अनिवार्य होगी। इसलिए हम पहले आई. पी. सी. की धारा 304 बी के साथ 1872 के अधिनियम की धारा 113 बी की जांच करेंगे। 1872 के अधिनियम की धारा 113 बी और आई. पी. सी. की धारा 304 बी को दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 43) द्वारा क़ानून की पुस्तक में जोड़ा गया था। दोनों प्रावधान एक तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किए गए हैंः .

> **“ a[113B. दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान।**
>
> जब सवाल यह होता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की थी।
>
> **स्पष्टीकरण**- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में है।](45 1860)।

[ए] दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम (1986 का 43), धारा 12 (19-11-86) द्वारा अंतःस्थापित।

“a [304B। दहेज मृत्यु।

(1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।]

[ए] दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम (1986 का 43), धारा 10 (19-11-1986) द्वारा अंतःस्थापित।

25. उपरोक्त प्रावधानों को नंगे पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि जब भी यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है, तो पहली बार में, यह 'दिखाया' जाना चाहिए कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। एक बार, यह 'दिखाया' जाता है कि कानूनी धारणा उत्पन्न होगी और न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत

परिभाषित दहेज मृत्यु का कारण बना था। निर्णयों के क्रम में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धारा 113 बी का अनुमान उत्पन्न होगा। यदि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत निर्धारित परिस्थितियों को स्थापित करने में सक्षम है।

26. **शेर सिंह @प्रताप बनाम हरियाणा राज्य मामले** ने **(2015) 3 एस. सी. सी. 724** में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास 1872 के अधिनियम की धारा 113 बी के तहत आने वाले "जल्द" और "माने गए" शब्दों के सही अर्थ और महत्व पर विचार करने का अवसर था। माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात पर भी विचार करने का अवसर मिला था कि आई. पी. सी. की धारा 304 बी के घटकों को साबित करने में अभियोजन पक्ष के लिए सबूत का कौन सा मानक लागू किया जाएगा और अपराध की समझी गई धारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त पर सबूत का मानक लागू किया जाएगा, जो अभियोजन पक्ष द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304 बी के घटकों को साबित करने के बाद उत्पन्न होता है।

27. **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार करने पर**, (2000) 8 एस. सी. सी. 382** और **सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य ने (2009) 14 एस.सी.सी. 415** में प्रतिवेदित किया जिनके **पैराग्राफ '16' में उनके प्रभुत्व निम्नानुसार हैंः**

> 16. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आई. पी. सी. की धारा 304-बी को उनके संबंधित कानूनों में एक साथ पेश किया गया था और इसलिए, यह सामान्य रूप से माना जाना चाहिए कि संसद ने जानबूझकर धारा 304-बी में "मानित" शब्द का उपयोग इस प्रावधान को दूसरों से अलग करने के लिए किया था। वास्तव में, हालांकि, एक समझदार और कानूनी रूप से पटना उच्च

न्यायालय सी. आर. देना लगभग असंभव है। इन प्रावधानों के लिए स्वीकार्य अर्थ, जब तक कि "दिखाया गया" शब्द का उपयोग "साबित" के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है और "माना" शब्द का उपयोग "समझा गया" शब्द के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमेय के रूप में किया जाता है। दीवानी और राजकोषीय कानून के क्षेत्र में, उन परिस्थितियों के समूह को दर्शाने के लिए "डीम" शब्द के सामान्य अर्थ को आयात करना मुश्किल नहीं है जो वास्तव में जो हैं उसके विपरीत माने जाते हैं। हालाँकि, आपराधिक कानून में, इस दृष्टिकोण को रोते हुए अपनाना अनुचित है। हमारे पास इस न्यायालय की संविधान पीठ का उच्च अधिकार है, दोनों त्रावणकोर-कोच्चि राज्य बनाम षण्मुघा विलास काजू कारखाना 8 और टी. एन. राज्य बनाम टी. एन.अरूरन शुगर लिमिटेड 9, न्यायालय से "डीम्ड" शब्द के उपयोग द्वारा लाए गए वैधानिक कल्पना के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने की आवश्यकता है ताकि कानून को पूरा प्रभाव दिया जा सके और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके। हम यह जोड़ सकते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि खंडन करने योग्य और साथ ही निर्विवाद अनुमान हैं, बाद वाले अक्सर एक डीमिंग प्रावधान के माध्यम से वास्तविकता के रूप में एक कृत्रिमता मानते हैं। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराना आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए घृणित है, भले ही उसका न तो इसे करने का इरादा था और न ही उसके कार्य में सक्रिय भागीदारी। यह गहन चिंतन के बाद है कि हम आई. पी. सी. की धारा 304-बी में "दिखाए गए" शब्द का अर्थ वास्तव में "साबित" के रूप में निकालना अनिवार्य समझते हैं। दूसरे शब्दों में, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है कि "दहेज मृत्यु" हुई है, अर्थात्ः

(i) कि किसी महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में जलने या शारीरिक रूप से घायल होने के कारण हुई है,

(ii) उसकी शादी के सात साल के भीतर,

(iii) और यह कि वह अपने पति या अपने पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई थी,

(iv) दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, और

(v) कि उसके साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न का दहेज की मांग के साथ एक कारण संबंध या एक जीवित संबंध बना रहा।

हम जानते हैं कि "जल्द" शब्द धारा 304-बी में मिलता है; लेकिन हम इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि यह आवश्यक रूप से इंगित करते हैं कि दहेज की मांग बासी या अतीत का विचलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304-बी के तहत मृत्यु या आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत आत्महत्या का निरंतर कारण होना चाहिए। एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा इन सह-अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित हो जाती है या दिखाई जाती है या साबित हो जाती है, यहां तक कि संभावना की अधिकता से भी, निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को अभियुक्त के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद उस पर सबूत का भारी बोझ स्थानांतरित हो जाता है और उसे उचित संदेह से परे अपने अपराध को दूर समर्पित के लिए सबूत पेश समर्पित की आवश्यकता होती है। हमें ऐसा लगता है कि संसद ने "मानित" शब्द का उपयोग करके जो इरादा किया था, वह यह था कि पति या उसके परिवार के सदस्यों को उनके अपराध से मुक्त करने के लिए केवल साक्ष्य की प्रधानता अपर्याप्त होगी। यह व्याख्या

> अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका प्रदान करती है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अभिधारणा भी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आई. पी. सी. की धारा 304-बी का उद्देश्य, हमारी राय में, विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की आत्महत्या या मृत्यु के मामले में सबूत की कमी या अनुपस्थिति का मुकाबला करना है। यदि "दिखाया" शब्द को सामान्य अर्थ देना है। तब होगा जब अभियोजन पक्ष को केवल अदालत में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जरूरी नहीं कि मौखिक बयान के माध्यम से, और फिर अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसरण किया जाए। यह प्रक्रिया सामान्य कानून प्रणालियों के लिए अज्ञात है, और सीआरपीसी के विचार से परे है।

28. कानूनी स्थिति की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस मामले में अभियोजन पक्ष उन आवश्यक तत्वों को साबित करने में सक्षम रहा है जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शेर सिंह** (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '16' में उजागर किया है।

29. इस मामले में, जहां तक शर्त संख्या **(i)** और **(ii)** का संबंध है, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से दर्ज कर सकता है कि यह जलने से असामान्य परिस्थितियों में हुई महिला की मृत्यु का मामला है। यह शादी के सात साल के भीतर एक महिला की मौत का भी मामला है। यह हमें इस प्रश्न की ओर ले जाएगा कि क्या अभियोजन पक्ष इस संभावना की अधिकता के माध्यम से भी साबित प्रस्तुत में सक्षम रहा है कि खंड **(iii)**, **(iv)** और **(v)** में निहित शर्तें मौजूद हैं ताकि अपीलार्थी के निर्दोष होने के प्रारंभिक अनुमान को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाए, जिससे उस पर सबूत का भारी बोझ

स्थानांतरित हो जाए, जिससे उसे उचित संदेह से परे अपने अपराध को दूर प्रस्तुत के लिए सबूत पेश प्रस्तुत की आवश्यकता हो।

30. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया है। यह हमें दिखाया गया है कि जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श '6') 27.10.2015 को 08:30 बजे सुबह तैयार की गई थी। अपोलो बर्न अस्पताल, कुम्हरार, कंकड़बाग में के. के. सिंह, पुलिस के एस. आई., अगमकुआं थाना (जांच नहीं की गई)। जाँच रिपोर्ट के कॉलम '6' में उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, यदि किसी ने गलत कार्य के बारे में संदेह उत्पन्न किया (वे परिस्थितियाँ यदि कोई जिससे किसी कुटकर्म को संदेह उत्पन्न हो।) कॉलम सं. '6' को केवल एक क्रॉस (**x**) चिह्न बनाया गया है जिसका अर्थ है कि एस. आई. के. के. सिंह द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करने के समय, इस अपीलार्थी द्वारा गलत कार्य/खेल का संदेह करने वाला कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है। कॉलम सं. जाँच रिपोर्ट के '8' में मृत्यु के कारण के बारे में गवाहों की राय के संबंध में जानकारी दी जानी है। कॉलम सं.8 के सामने में भी केवल यह जानकारी दी गई है कि मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आग लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस प्रकार, जाँच रिपोर्ट (प्रदर्श '6') सूचना देने वाले या जाँच गवाह (पीडब्लू-1) द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ उठाए गए किसी भी संदेह का संकेत नहीं देती है।

31. आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने घटना स्थल से कोई वस्तु जब्त नहीं की थी और उक्त स्थान की कोई तस्वीर नहीं ली गई थी। इससे यह भी संदेह पैदा होता है कि क्या पीडब्लू-8 ने कभी घटना स्थल का दौरा किया था। पीडब्लू-4 की जाँच मुख्य परीक्षक इंगित करती है कि पीड़ित और अपीलार्थी के बीच विवाह हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था। अपने *फरदबेयान* में, पीडब्लू-4 ने कहा है कि उसने शादी में 10 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शादी के समय दहेज की कोई मांग की गई थी। अपने जाँच प्रमुख में भी पीडब्लू-4 ने शादी के समय दहेज की मांग का

आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षक के पैराग्राफ '1' में कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी क्षमता के अनुसार हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार की थी और शादी के बाद उनकी बेटी अपने पति के साथ ससुराल गई थी और उसके बाद कुछ दिनों तक ठीक रही।

32. हालाँकि, अपने *फ़र्दबेयान* में, उसने यह नहीं कहा है कि उसके *ससुराल* जाने के एक हफ्ते बाद, उसके पति, सास और ससुर ने उसे 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, लेकिन जाँच-पड़ताल में, पीडब्लू-4 ने एक बयान दिया है कि कुछ दिनों तक अच्छी तरह से रहने के बाद, उसके एक हफ्ते बाद, उसके पति, सास और ससुर द्वारा 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी सूचना उसकी बेटी फोन पर दे रही थी। इस मामले में सास और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। पीडब्लू-4 ने आगे कहा है कि उसकी शादी के एक महीने बाद, उसकी बेटी अपने पति, सास और ससुर के साथ मुज़फ़्फ़रपुर नया तोला में रेलवे क्वार्टर में स्थानांतरित हो गई थी लेकिन आरोपी व्यक्ति 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग करते रहे।

33. इस न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में पीडब्लू-4 का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है यदि इसे उसके बाद के बयान के साथ देखा जाए। पीडब्लू-4 के अनुसार, नम्रता (मृतक) को सिंडिकेट बैंक में पाकुड़ स्थानांतरित कर दिया गया था और वहाँ से उसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ वह अपने पति के साथ रह रही थी। अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा है कि शादी के बाद, नम्रता भगवानपुर शाखा में काम करती थी और रेलवे क्वार्टर, नया तोला मुज़फ़्फ़रपुर में रह रही थी। इससे पता चलता है कि नम्रता (मृतक) आत्मनिर्भर थी, वह अपनी शादी से पहले से ही बैंक में काम कर रही थी और अपने *ससुराल* में रहते हुए काम कर रही थी। पीडब्लू-4 ने कहा है कि छुट्टियों और त्योहारों के दौरान वह उसके घर भी जाती थी। इससे पता चलता है

कि नम्रता अपनी पसंद का जीवन जी रही थी। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि अपीलार्थी का परिवार उसके वेतन से होने वाली कमाई में भाग लेने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। वह छुट्टियों और त्योहारों के दौरान स्वतंत्र रूप से अपने पिता के घर जा रही थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पीडब्लू-4 ने यह भी कहा है कि जब नम्रता को भगवानपुर से पाकुड़ स्थानांतरित किया गया था, तो वह पाकुड़ में दो महीने तक होटल में रही थी और इस दौरान वह प्रशिक्षण के लिए कोलकाता भी गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। पीडब्लू-4 ने कहा है कि इन दो महीनों की अवधि के दौरान, उनके पति पाकुड़ में उनसे मिलने आए थे। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पाकुड़ में, यह अपीलार्थी झगड़ा या दहेज की मांग में लिप्त था। यह भी सबूत में आया है कि नम्रता (मृतक) की छोटी बहन की शादी की बात चल रही थी और दूल्हे की तरफ से लोग उसे देखने आ रहे थे। इस अवसर पर भी अपीलार्थी नम्रता (मृतक) के साथ मुज़फ़्फ़रपुर गया था। वे दोनों 24.10.2015 को मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचे और 25.10.2015 को लौटे। पीडब्लू-4 का बयान कि उन्हें लगभग 4 बजे शाम 26.10.2015 को नम्रता का फोन आया और उसने उससे कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उसे मार दिया जा सकता है, आई. ओ. द्वारा असत्यापित रहा।

34. यह आगे दर्शाता है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी (मृतक) के बीच किसी अन्य प्रकार का विवाद हो सकता है लेकिन कम से कम दहेज की मांग का कोई मुद्दा नहीं था। नम्रता की मृत्यु क्यों और कैसे हुई, यह एक रहस्य बना रह सकता है, लेकिन इस अदालत के लिए, यह प्रतीत होता है कि इस संभावना की प्रचुरता से भी यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दहेज की कोई मांग की गई थी और नम्रता को उसकी मृत्यु से पहले दहेज की किसी भी मांग के संबंध में उसके पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। *शव परीक्षण प्रतिवेदन* (प्रदर्श '4') और डॉक्टर (पीडब्लू-7) का साक्ष्य कहीं भी मृतक के व्यक्ति पर हिंसा का कोई निशान नहीं दिखाता है। इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस मामले में अभियोजन यह

संभावना की प्रचुरता से साबित करने में सक्षम नहीं था कि घटना से कुछ समय पहले, नम्रता के साथ दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता का व्यवहार किया गया था।

आवास, पंजीकरण और प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में देरी

35. इस मामले में सूचना देने वाले से पीडब्लू-4 के रूप में पूछताछ की गई है। अपनी गवाही में, पीडब्लू-4 ने कहा है कि पुलिस ने अस्पताल में ही उसका *फर्दब्यान* 27.10.2015 को दर्ज किया था, लेकिन उसे फर्दब्यान नहीं पढ़ा गया था और उसने उसे पढ़े बिना उसी पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था। अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि वह 11 बजे रात्रि 26.10.2015 को अपोलो बर्न अस्पताल पहुंचे थे। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 27.10.2015 को *शव का परीक्षण* किया गया और उसी दिन उसका शव प्राप्त करने के बाद, उसने गुलबीघाट में शव का अंतिम संस्कार किया और शाम को ही मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी जिरह में आगे कहा है कि वह तीन दिन बाद पटना वापस आया था। अपने *फरदबेयान* (प्रदर्श '1/3') में, मुखबिर (पीडब्लू-4) ने कहा है कि उसकी बेटी नम्रता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसकी हत्या कर दी गई है और उसे पड़ोसियों ने घटना के बारे में सूचित किया था, लेकिन परीक्षण के दौरान, उसने खुलासा किया कि 26.10.2015 को लगभग 09 बजे रात्रि, उन्हें गंगा परिसर के निवासी गौतम का फोन आया और उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी जल गई है। गौतम से पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की गई है और वह मुकदमे के दौरान नहीं आया है। सूचना देने वाले का *फरदबेयान* केवल अगली तारीख यानी 27.10.2015 को 08 बजे सुबह दर्ज किया गया था, इस प्रकार, सूचना देने वाले के फरदबेयान की रिकॉर्डिंग में कम से कम नौ घंटे की देरी होती है। उनके बयान से यह स्पष्ट है कि 28.10.2015 को उनका आगे का बयान पुलिस के एस. आई. विजय कुमार मिश्रा (पीडब्लू-8), कंकड़बाग द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। अगमकुआं पुलिस स्टेशन के एस. आई. के. के. सिंह द्वारा दर्ज फरदेब्यन को कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में 18:45 बजे शाम

28.10.2015 को प्राप्त किया गया था और यह एक साथ पंजीकृत किया गया था। पीडब्लू-8 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जाँच संभालने के बाद उसने पीडब्लू-4, पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 का बयान दर्ज किया जो मौजूद थे लेकिन रात के समय के कारण वह उस दिन घटना स्थल पर नहीं जा सका और वह 29.10.2015 को वहाँ गया, उसने 29.10.2015 को सूचना देने वाले (पीडब्लू-4) की पहचान पर घटना स्थल का निरीक्षण किया लेकिन पीडब्लू-4 ने कहा है कि वह निरीक्षण के समय घटना स्थल पर नहीं था।

36. पीडब्लू-4 और पीडब्लू-8 के साक्ष्य भौतिक विवरणों पर एक दूसरे के विपरीत हैं। पीडब्लू-4 में कहा गया है कि वह 27.10.2015 को ही शव का अंतिम संस्कार करने के बाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए और तीन दिन बाद वापस आ गए, इसलिए, पीडब्लू-8 का बयान कि उन्होंने मुखबिर और प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने के बाद गवाह का आगे का बयान दर्ज किया, लेकिन घटना स्थल के सत्यापन के लिए उस दिन नहीं जा सके और 29.10.2015 को उक्त स्थान पर गए, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सूचना देने वाला 28.10.2015 को पटना में मौजूद नहीं था। वह तीन दिनों के बाद वापस आया जिसका अर्थ था कि वह 30.10.2015/31.10.2015 को पटना पहुँचा। विद्वत विचारण न्यायालय के अभिलेखों से पता चलता है कि पहला आदेश 31.10.2015 को दर्ज किया गया है जो निम्नानुसार हैः .

"31.10.2015 – आरोपी समीर कुमार सिन्हा के खिलाफ धारा 304 (बी) आई. पी. सी. के तहत कंकड़बाग थाना केस संख्या- 73415 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

देखा है। अंतिम प्रपत्र प्राप्त होने के बाद इस मामले को दर्ज करें।

(आदेशित)

"न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना"

37. इसलिए इस अदालत ने अभिलेखों से पाया कि न केवल *फरदबेयान* को दर्ज करने में पर्याप्त देरी हुई, बल्कि उक्त *फरदबेयान* लगभग 35 घंटे के बाद कंकड़बाग थाना पहुंचा और 16:45 बजे शाम 28.10.2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन यह 31.10.2015 को तीन दिनों के बाद विद्वान न्यायिक दंडाधिकार की अदालत में पहुंच गया, इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है।

38. हम पाते हैं कि आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने प्राथमिकी भेजने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि कोई बीच की छुट्टी थी या किसी भी कारण से आई. ओ. के नियंत्रण से परे थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन विद्वान दंडाधिकारी को 24 घंटे की वैधानिक अवधि के भीतर नही भेजी जा सकी। **रमेश बाबूराव देवस्कर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला (2007) 13 एस. सी. सी. 501** में दर्ज किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः .

> **"**20. दंड प्रक्रिया संहिता कुछ आंतरिक और बाहरी जाँचों का प्रावधान करती है; उनमें से एक संबंधित दंडाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति है। यह विवाद में नहीं है कि इस तरह के गंभीर मामले में, दंडाधिकारी को चार दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हुई थी। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में आदेश दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम दंडाधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यह विवादित नहीं है कि यह घटना जिला मुख्यालय के पास हुई थी। चार दिन के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों भेजी गई, इसका कोई कारण नहीं हो सकता है। *(जगदीश मुराव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 देखें।* **"**

39. (2001) 9 एस. सी. सी. 704 में रिपोर्ट किए गए **जंग सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में, उनके अधिपत्य द्वारा इस प्रकार अवलोकन किया गयाः

> "फिर से, यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन 26-7-1975 को दर्ज की गई, और यह 29-7-1975 को दंडाधिकारी के पास पहुंची, और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि दंडाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में इतनी देरी क्यों हुई है। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 1 की प्रतिपरीक्षा में आंतरिक रूप से सामने लाई गई सामग्री हमें यह मानने के लिए राजी करती है कि उक्त पी. डब्ल्यू. 1 को, किसी भी तरह की कल्पना से, एक सच्चा गवाह नहीं माना जा सकता है, जिसकी गवाही पर इतने सारे अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। ....."

40. वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह पाया गया है कि पटना के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्राथमिकी भेजने में तीन दिनों की अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होगी।

41. हाल ही में, **(2024) 2 एस. सी. सी. 176** में रिपोर्ट किए गए **सेकरन बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क पर ध्यान दिया है कि देर से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, हालांकि, यह माना गया है कि इसे स्वयं और बिना किसी और चीज़ के सभी मामलों में अदालतों के दिमाग में अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक विशेष मामले की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए एक यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या प्राथमिकी दर्ज करने में अस्पष्टीकृत देरी घटना का एक रंगीन संस्करण देने के लिए एक विचार के बाद है, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को कम करने

के लिए पर्याप्त है। इस मामले में, हम पाते हैं कि यह न केवल प्राथमिकी दर्ज करने में देरी है, बल्कि बाद की घटनाएं जैसे कि प्राथमिकी दर्ज करने में 35 घंटे की देरी और फिर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्राथमिकी भेजने में तीन दिनों की अस्पष्ट देरी ऐसी हैं कि वे अभियोजन पक्ष के कथन की विश्वसनीयता को धूमिल करने के लिए पर्याप्त हैं और यह एक संदेह पैदा करता है क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला एक विचार के बाद का परिणाम है।

42. यह अभिलेखों से आगे पता चलता है कि आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी की जांच नहीं की थी।

43. इस अदालत ने पाया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से चार महीने बाद, खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) को यह कहते हुए पेश किया गया है कि वह नौकरानी के रूप में काम कर रही थी और एक चश्मदीद गवाह है। पीडब्लू-4 ने अपने *फ़र्दबेयान* में पीडब्लू-5 की उपस्थिति के बारे में खुलासा नहीं किया था। उसने कहा है कि 26.10.2015 की उक्त रात को, नम्रता (मृतक) को इस अपीलार्थी द्वारा प्रताड़ित किया गया था और पैसे को लेकर विवाद था। पीडब्लू-5 ने घटना से ठीक पहले और घटना के बाद की परिस्थितियों के गवाह के रूप में गवाही दी है। उसने अपीलार्थी को मृतक को आग लगाते नहीं देखा था। उसने अपने प्रमुख परीक्षण में कहा है कि उक्त रात को, अपीलार्थी ने मृतक को हाथ और मुट्ठी से मारा था। खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) एक बाल गवाह है। घटना के समय वह केवल '9' वर्ष की थी। वह दावा करती है कि *दीदी* उसे पढ़ाई के लिए लाई थी लेकिन उसे किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया था। *फरदबेयान* (प्रदर्श '1/3') में, पीडब्लू-4 ने फ्लैट (पीओ) में पीडब्लू-5 की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया है, लेकिन बाद में पीडब्लू-4 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) एक नौकरानी थी और वह वहां मौजूद थी, जब वह अस्पताल पहुंची तो वह भी अस्पताल में मौजूद थी।

26.10.2015 (रात) को पीडब्लू-4 ने पुलिस के समक्ष या मुकदमे के दौरान अपने बयान में यह नहीं कहा कि खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) ने उसे उस घटना के बारे में बताया था जो 26.10.2015 को हुई थी, लेकिन बाद में, चार महीने बाद, खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) को थाना में पेश किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। हालाँकि पीडब्लू-4 ने अपने आगे के बयान में पीडब्लू-5 का नाम लिया, फिर भी उसे आई. ओ. के सामने लाने में चार महीने लग गए। (पीडब्लू-8)। उन्हें 25.02.2016 को विद्वान दंडाधिकारी की अदालत में ले जाया गया, जहाँ धारा 164 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनका बयान दिया गया। (आपत्ति के साथ प्रदर्श '7') दर्ज किया गया है।

44. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने वाले विद्वान दंडाधिकारी ने बस यह दर्ज किया है कि "गवाहों से कुछ सवाल पूछने के बाद, मेरा मानना है कि वह प्रश्नों की प्रकृति को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम हैं। **"** हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विद्वान दंडाधिकारी ने एक बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक वास्तविक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की है। पी. रमेश बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक **(2019) 20 एस. सी. सी. 593 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः**

> 13. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 संबंधित है। न्यायालय के समक्ष गवाही देने की किसी व्यक्ति की क्षमता के साथ, शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 में बारह वर्ष से कम आयु के बाल गवाहों के अपवाद के साथ सभी गवाहों को शपथ लेने या पुष्टि करने की आवश्यकता है। इसलिए, यदि अदालत संतुष्ट हो जाता है कि बारह वर्ष से कम आयु का बाल गवाह एक सक्षम गवाह है, तो ऐसे गवाह से बिना शपथ या पुष्टि के पूछताछ की जा सकती है। दत्तू रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 5 में नियम कहा गया था, जहां इस न्यायालय ने बाल गवाहों के संबंध में इस प्रकार निर्णय दिया

थाः(एससीसी पृष्ठ 343, पैरा "5) 5.... एक बाल गवाह यदि तथ्यों को गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है और ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम हो और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को केवल यह सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और उसे पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है।

14. एक बच्चे को पहले एक सक्षम गवाह होना चाहिए, तभी उसका बयान स्वीकार्य है। यह नियम व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 6 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में निर्धारित किया गया था, जिसमें यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः(एस. सी. सी. ऑनलाइन यूएस एस. सी. पैरा 5)

5. ... जबकि कोई भी केवल दो या तीन साल के शिशु को गवाह के रूप में बुलाने के बारे में नहीं सोचेगा, कोई सटीक उम्र नहीं है जो योग्यता के सवाल को निर्धारित करती है। *यह बच्चे की क्षमता और बुद्धि, सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर की उसकी सराहना के साथ-साथ पहले वाले को बताने के उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो प्रस्तावित गवाह को देखता है, उसके तरीके, उसके स्पष्ट कब्जे या खुफिया जानकारी की कमी को नोटिस करता है, और किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ के दायित्वों की उसकी समझ को प्रकट करेगा।* इनमें से कई

मामलों को अभिलेख में चित्रित नहीं किया जा सकता है, परीक्षण न्यायाधीश के निर्णय को समीक्षा पर तब तक बाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि जो संरक्षित है उससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि यह गलत था। "

(जोर दिया गया)

15. रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य में 7, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पीपी. 67-68, पैरा 7)

"7.... *इस सवाल पर निर्णय कि क्या बाल गवाह के पास पर्याप्त खुफिया जानकारी है, मुख्य रूप से परीक्षण न्यायाधीश पर निर्भर करता है जो उसके व्यवहार, उसके स्पष्ट कब्जे या खुफिया जानकारी की कमी को नोटिस करता है, और उक्त न्यायाधीश किसी भी जांच का सहारा ले सकता है जो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ के दायित्व की अपनी समझ का खुलासा करने की प्रवृत्ति रखता है। हालाँकि, निचली अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बाधित किया जा सकता है यदि अभिलेखों में जो संरक्षित है, उससे यह स्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष गलत था।* यह सावधानी आवश्यक है क्योंकि बाल गवाह शिक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं और अक्सर विश्वास की दुनिया में रहते हैं। हालांकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह खतरनाक गवाह होते हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित होने, आकार देने और ढाले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यह भी एक स्वीकृत मानदंड है कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसमें सच्चाई का प्रभाव है, तो बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने के तरीके में कोई बाधा नहीं है।

(जोर दिया गया)

> 16. बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए, न्यायाधीश को उसकी या उसकी राय बनानी होती है। न्यायाधीश एक बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है और बुद्धि और ज्ञान की डिग्री के बारे में कोई सटीक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो बच्चे को एक सक्षम गवाह प्रदान करेगा। एक बाल गवाह की क्षमता का पता उसे पूछताछ करके लगाया जा सकता है ताकि वह गवाह की घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगा सके। आपराधिक कार्यवाही में, किसी भी उम्र का व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है यदि वह (**i**) गवाह के रूप में रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है; और (**ii**) उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर दे सकता है जिन्हें समझा जा सकता है। कम उम्र के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसके पास प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है। एक बच्चा तभी अक्षम हो जाता है जब अदालत यह मानती है कि बच्चा प्रश्नों को समझने और सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उनका उत्तर देने में असमर्थ था। यदि बच्चा अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझता है और उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देता है, तो यह हो सकता है। यह माना जाता है कि वह जाँच के लिए एक सक्षम गवाह है।

45. हाल ही में एक निर्णय में, इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने **रूदल चौपाल बनाम बिहार राज्य के मामले में 2024 (2) बी. एल. जे. 331 (एच. सी.)** में कहा कि इससे पहले एक बच्चे के साक्ष्य को दर्ज करना, एक न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में

है। दंडाधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि बच्चा प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है।

46. हम पाते हैं कि न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीडब्लू-5 का बयान दर्ज करने वाले विद्वान दंडाधिकारी की सुनवाई के दौरान जांच नहीं की गई है, बल्कि विद्वान निचली अदालत ने पीडब्लू-5 का साक्ष्य दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच बिल्कुल नहीं की है। यह एक रहस्य बना हुआ है कि पीडब्लू-5, जो 26.10.2015/27.10.2015 को अस्पताल में मौजूद थी, ने उक्त शाम को फ्लैट के अंदर हुई घटना का खुलासा पीडब्लू-4 या पुलिस के एस. आई. के. के. सिंह को क्यों नहीं किया, जिन्होंने पीडब्लू-4 के *फर्दब्यान* को दर्ज किया और चार महीने बाद उसे गवाह के रूप में क्यों पेश किया गया। यह पीडब्लू-8 के साक्ष्य के साथ भी देखा जा सकता है, जिसने पैराग्राफ '3' में कहा है कि उसने खुशी कुमारी (पीडब्लू-5) का बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया था और उसने उसके सामने कहा था कि नम्रता ने खुद को आग लगा ली थी (उसकी जिरह का पैराग्राफ '12')।

47. पीडब्लू-5 के साक्ष्य के अवलोकन से आगे पता चलता है कि वह मृतक और अपीलार्थी के साथ मुजफ्फरपुर गई थी। उसने कहा है कि ट्रेन में दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था और वे ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो से घर गए थे। इस गवाह का कहना है कि मृतक के घर पहुंचने के बाद वह अकेले अपने घर चली गई थी। उसने कहा है कि मुज़फ़्फ़रपुर में, अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने पूरे बयान में यह नहीं कहा है कि उसने कभी भी अपीलार्थी द्वारा 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग के बारे में सुना था। पीडब्लू-5 के साक्ष्य में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनके अनुसार, यह अपीलार्थी झगड़े के बाद उसी दिन मुजफ्फरपुर से चली गई थी और वह अपने घर चली गई थी जहाँ वह अपने माता-पिता के साथ दो दिनों तक रही थी। यदि पीडब्लू-5 25.10.2015 से अपने माता-पिता के साथ दो दिनों तक

रहती है, तो 26.10.2015 को फ्लैट में उसकी उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। उसने खुद अपनी जिरह के पैरा '8' में कहा है कि उसके बयान के लिए, उसे उसके माता-पिता द्वारा 2 से 3 महीने बाद पुलिस के सामने लाया गया था। यह केवल इस न्यायालय के विचारों को मजबूत करता है कि पीडब्लू-5 किसी भी परिस्थिति की चश्मदीद गवाह नहीं है जिससे 26.10.2015 की घटना हुई, वह घटना के स्थान पर मौजूद नही थी और उसे इस मामले में शिक्षण के बाद एक गवाह के रूप में पेश किया गया है। 1872 के अधिनियम की धारा 134 ने गवाहों की मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, वे हैंः- **(i)** पूरी तरह से विश्वसनीय, **(ii)** पूरी तरह से अविश्वसनीय और **(iii)** न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। उनका साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह की श्रेणी में आएगा जैसा कि 1872 के अधिनियम की धारा 134 के तहत परिकल्पित है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह सबूत की गुणवत्ता है जो मात्रा को मायने नहीं रखती है।

48. हमारा मानना है कि पीडब्लू-5 एक प्रशिक्षित बाल गवाह है जिसे बहुत देर से पेश किया गया है और उसकी उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है।

49. जहाँ तक अन्य गवाहों की बात है जैसे विमलेश कुमार (पीडब्लू-1), कीर्ति प्रसाद वर्मा (पीडब्लू-2) और नितीश कुमार सिंह (पीडब्लू-3) का संबंध हैं, वे सूचना देने वाले की बेटी की मृत्यु का कारण दिखाने वाली परिस्थितियों के गवाह नहीं हैं। ये गवाह मुखबिर (पीडब्लू-4) से संबंधित हैं। उन सभी के बयान में एक बात समान है कि विवाह के समय दोनों पक्षों के बीच बिना किसी विवाद या मतभेद के विवाह संपन्न हुआ था। उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि शादी के समय दहेज की कोई मांग की गई थी। वास्तव में, यह पीडब्लू-4 के मामले में भी नहीं है कि अपीलार्थी ने शादी के समय कोई मांग की थी। पीडब्लू-1 ने कहा है कि नम्रता शादी के बाद उसके *ससुराल* गया था, लेकिन एक महीने के बाद, उसके *ससुराल* वालों ने उसे 2 लाख रुपये

और एक मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जो विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि नम्रता शादी से पहले सिंडिकेट बैंक की कर्मचारी थी और यह समझना मुश्किल है कि अगर शादी के समय कोई मांग नहीं की गई थी तो अपीलकर्ता अपनी पत्नी को 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग के लिए प्रताड़ित क्यों करेगा। पीडब्लू-1 ने इस हद तक कहा है कि शादी के बाद नम्रता खुशी-खुशी अपने *ससुराल* गई थी और लगभग एक महीने से वह अपने ससुराल में रह रही थी और अपीलार्थी के ग्राम से मुज़फ़्फ़रपुर में अपने काम में शामिल होती थी। इससे यह भी पता चलता है कि नम्रता को उनके *ससुराल* से पूरा सहयोग मिल रहा था और उन्हें अपने काम में शामिल होने के लिए अपने *ससुराल* से मुजफ्फरपुर जाने की अनुमति दी गई थी। पीडब्लू-1 का आवास मुजफ्फरपुर में नम्रता के घर से केवल दो किलोमीटर की दूरी पर था। वह नम्रता के चाचा हैं लेकिन वह यह नहीं कहते हैं कि किसी भी स्तर पर नम्रता ने उनसे दहेज की मांग या यातना के संबंध में शिकायत की थी।

50. पीडब्लू-2 पीडब्लू-4 का सह-भाई है जिसके हस्तक्षेप पर शादी की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने अपने जाँच प्रमुख में यह भी कहा है कि गड़बड़ी लगभग एक महीने के बाद शुरू हुई और उन्हें पीडब्लू-4 द्वारा 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग के बारे में बताया गया था। इस गवाह ने यह भी नहीं कहा है कि नम्रता मांग को पूरा न करने के कारण उसे की जा रही यातना और मांग के बारे में कभी उसे बताया था।

51. नितीश कुमार (पीडब्लू-3) ने यह भी नहीं कहा है कि किसी भी स्तर पर नम्रता ने उसे दहेज की मांग और यातना के बारे में बताया था।

52. इस मामले में शव का परीक्षण करने वाले डॉक्टर की जांच पीडब्लू-6 के रूप में की गई है, उन्हें मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं: .

> **"(i)** खोपड़ी के बाल हस्ताक्षरित किरोसीन तेल जैसी गंध जो चेहरे, गर्दन, दोनों ऊपरी अंगों, धड़ के सामने और पीछे, नितंब, दोनों निचले अंगों, पैरों के तलवे को छोड़कर कई स्थानों पर दिखाई देने वाले लालिमा और काली त्वचा के साथ डर्मोपिडर्मल जलन घाव की गंध में देखी जाती है।
>
> **((ii)** विच्छेदन पर-दोनों फेफड़े भीड़भाड़ वाले थे। दाहिना हृदय कक्ष भरा हुआ था और खाली छोड़ दिया गया था। पेट में लगभग 100 मि. ली. खीचड़ी होती है। पेट का विसरा भीड़भाड़ वाला था। गर्भाशय गर्भवती नहीं थी। मूत्राशय खाली था। मस्तिष्क और उसके मेनिन्जेस भीड़भाड़ वाले थे।
>
> राय-ऊपर उल्लिखित जलने की चोटें प्रकृति में पूर्व-मृत्यु थीं। मौत जलने की चोटों और आग की लपटों के कारण हुई जटिलताओं के कारण हुई। मृत्यु के बाद का समय 4 से 12 घंटे के भीतर पोस्टमॉर्टम परीक्षा के समय था।
>
> मेरी कलम में उपरोक्त पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित मेरे हस्ताक्षर। "

53. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि पैरों की उंगलियों को छोड़कर मृतक का पूरा शरीर जला हुआ पाया गया था। ऐसी चोटें तब लग सकती हैं जब कोई व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में जल जाता है। चारों तरफ से शव जला दिया गया था। पीडब्लू-6 ने कहा है कि वह यह नहीं कह सकते कि इस तरह की चोटें आत्महत्या के मामले में हो सकती हैं या नहीं। उन्होंने अपनी जिरह के पैराग्राफ '3' में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल डालता है तो आग पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेगी। उन्हें पेट में 100 मिलीलीटर *खीचड़ी* मिली थी। पीडब्लू-6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि नम्रता को सोते समय आग नहीं लगाई गई थी। अगर सोने की स्थिति में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला जाता या वह जलने के समय विरोध करती, तो डॉक्टर को

कुछ अन्य एंटी-मॉर्टम चोटें जरूर मिली होंगी, लेकिन इस मामले में मृतक के शरीर पर कोई अन्य एंटी-मॉर्टम चोट नहीं मिली है। अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के पैटर्न के साथ *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट से पता चलता है कि मुजफ्फरपुर में अपने माता-पिता के घर से लौटने पर नम्रता खुश नहीं थी, हालांकि उसने कुछ खाना खाया था, लेकिन कुछ परेशान हालत में, उसने कठोर कदम उठाया। उसके शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं है और जब तक अपीलार्थी उसे बचाने आया, वह बुरी तरह से जल चुकी थी। बचाने के लिए, अपीलार्थी को भी जला दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। अपीलार्थी को अपोलो बर्न अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी का भी उसी अस्पताल में इलाज किया गया था। आई. ओ. ने अपने बयान में कहा है कि उनके द्वारा दर्ज किए गए अपने-अपने बयानों में एक राम चरित्र दास जो इमारत में गार्ड हैं और उक्त अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या- 401 के निवासी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा था कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी दोनों वहां खुशी-खुशी रह रहे थे और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था। यह ज्ञात नहीं है कि आई. ओ. ने इस मामले में राम चरित्र दास और मिथलेश कुमार सिंह को आरोप पत्र गवाह क्यों नहीं बनाया, हालांकि, इस संबंध में आई. ओ. के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है।

54. विद्वत निचली अदालत ने यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि राम चरित्र दास और मिथलेश कुमार को आरोप पत्र में गवाह के रूप में नामित नहीं किया गया है, इसलिए उनके बयान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी और मुकदमे में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में भरोसे को **मल्कियत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1991) 4 एस.सी.सी. 341** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है और **मलकियत सिंह** (उपरोक्त) के मामले में फैसले को देखते हुए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कोई कानून नहीं पाते हैं कि आई. ओ. (पीडब्लू-8) राम चरित्र दास और मिथलेश कुमार द्वारा दिए गए बयानों

पर गौर नहीं किया जा सकता है। यदि आई. ओ. ने आरोप पत्र में उन दो व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया जिनकी जांच की गई थी और आई. ओ. के समक्ष जांच के दौरान बयान दिया था, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि आई. ओ. को वे दो गवाह नहीं चाहिए थे जो अभियोजन पक्ष के हितों के खिलाफ गवाही देने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहे थे। हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन दो गवाहों ने कहा था कि पत्नी और पति दोनों खुशी से रह रहे थे और अपीलार्थी उसे एम्बुलेंस द्वारा अपोलो बर्न अस्पताल ले गया था। ये दो गवाह जिनके बारे में आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने कहा है कि वे घटना के तुरंत बाद की परिस्थितियों के गवाह हैं और इस संबंध में पीडब्लू-8 के बयान को खारिज करने का कोई कारण होगा।

55. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि बचाव पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की। डी. डब्ल्यू.-1, मिथिलेश कुमार फ्लैट संख्या- 406 जिसमें अपीलार्थी मृतक के साथ रह रहा था। उन्होंने कहा है कि फ्लैट अपीलार्थी को सितंबर, 2015 में किराए पर दिया गया था। इस गवाह के अनुसार, पति और पत्नी दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। यह अपीलार्थी 08 बजे रेलवे फैक्ट्री, मरहौरा में अपने काम पर 08.30 बजे सुबह जाता था और नम्रता सुबह 09 बजे अपने काम पर जा रही थी। वे दोनों काम कर रहे थे और शाम को आते थे। 26.10.2015 को, इस अपीलार्थी को आग बुझाते हुए देखा गया और वह चिल्ला रहा था। उन्होंने कहा है कि फ्लैटों के लोग वहां आए थे और नम्रता को बचाने के प्रयास में इस अपीलार्थी को भी जलने की चोटें आई थीं। उनके प्रति परीक्षण उन्होंने कहा है कि घटना के समय, वह गंगा परिसर में ही थे और *हल्लों* पर, वह घटना स्थल पर पहुंचे थे। उसने अपीलार्थी को आग बुझाने की कोशिश करते देखा था, नम्रता खड़ी हालत में थी। एक अन्य गवाह निर्मला देवी (डी. डब्ल्यू.-2) हैं, जिन्होंने कहा है कि यह अपीलार्थी उनके गोविंद चक स्थित घर में किरायेदार था, जहाँ वे लगभग दो साल तक रहे थे। उन्होंने पति और पत्नी के बीच अच्छे संबंधों के बारे में भी बताया है। संतोष

कुमार सिंह (डी. डब्ल्यू.-3) अपीलार्थी का एक सहयोगी है जिसने कहा है कि वह अपीलार्थी के साथ रेलवे कारखाने में काम कर रहा था और उसने कहा है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए था। रेणु देवी (डीडब्ल्यू-4) और रिंकी देवी (डीडब्ल्यू-5) अपीलार्थी की दो बहनें हैं। दोनों ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे। डी. डब्ल्यू.-5 ने कहा है कि घटना से दो दिन पहले, वे दोनों मुज़फ़्फ़रपुर गए थे जहाँ कुछ विवाद था और नम्रता के पिता अपनी छोटी बेटी की शादी के उद्देश्य से **Rs**.50,000/- की राशि की मांग कर रहे थे, जिसके कारण नम्रता परेशान थी और उसने आत्महत्या कर ली।

56. विद्वत निचली अदालत ने बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों को कोई विश्वसनीयता नहीं दी है और चिकित्सा दस्तावेज जिन्हें प्रदर्श 'ए सीरीज' और प्रदर्श 'बी सीरीज' के रूप में चिह्नित किया गया था।

57. इस संबंध में, हम पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8 की मौखिक गवाही से पाते हैं कि उन्होंने कहा है कि इस अपीलार्थी को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीडब्लू-8 ने अपने बयान के पैराग्राफ '7' में कहा है कि इस अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह घायल हो गया था। पीडब्लू-8 ने अस्पताल में अपीलार्थी का बयान दर्ज किया था, उसने अपीलार्थी की छुट्टी पर्ची प्राप्त की थी जिसे उसने केस डायरी के साथ संलग्न किया था और उसे पहचान के लिए 'एक्स' के रूप में चिह्नित किया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि अभिलेखों पर यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी नम्रता को बचाने की कोशिश की थी, जब वह जल रही थी और उक्त प्रयास में उसे चोटें आई थीं। विद्वत विचारण न्यायालय के पास इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।

58. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हमारा विचार है कि विद्वत निचली अदालत ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की

धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने पहली बार में यह स्थापित नहीं किया है कि नम्रता को उसके पति (अपीलकर्ता) द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था और घटना से कुछ समय पहले, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और परेशान किया गया था। इसलिए, इस मामले में, बचाव पक्ष द्वारा खंडन के भारी बोझ की आवश्यकता वाली कानूनी धारणा उत्पन्न नहीं होगी।

59. नतीजतन, दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसे अपने जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(जी. अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

ऋषि/सिद्धार्थ -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।